polists out of it. Here is an industry which is continuously being profitable and you say, we cannot nationalise it. I want to know when the time will come, what is the criterion for taking over these mills and whether you have a policy by which monopolies will be curbed and the interests of the poor man will be served.

I hope the minister will direcfly answer my questions without going round and round.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: My hon. friend has said that the voluntary price agreement has totally failed. I do not share his view, nor his figures. I have already said that the price recommended by the Tariff Commission in September, 1970 for nylon 15 denier was Rs 73.80.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN. I have said that the voluntary price agreement is there. The price will be written in the bills. But when the weaver goes to the market apart from what is written in the bill, he has got to pay black money to get the yarn.

PROF D P. CHATTOPADHYAYA. I have said that in between September, 1970 and January, 1973 there was no question of price increase I have already said that because of the scarcity of the commodity there has been some malpractice. I have also said very clearly that some units have went out of the voluntary agreement and action is being taken against them I have already said that profit motive was evident from the high dividends declared by some companies. In the formula that we are evolving we will take care of these things so that the high profit rate is not allowed. Then he asked a question about nationalisation, which is a big question. There are two considerations for nationalisation. One is that it must be in the priority sector. Here it does not come under the priority sector. Secondly, if in the larger interest of the people and the employees some sick mills have to be taken over, they will be taken over.

SHRI PILOO MODY: Thirdly, the most important thing is that you do not know how to manage them.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA. I will solicit your help in this matter.

I can only say that whatever voluntary statutory agreement we arrive at will be uniformly applicable and nobody will be exempt from it.

13.13 hrs.

RE. ATROCITIES COMMITTED ON HARIJAN WOMEN IN BIHAR —contd.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have not allowed any adjournment motion .

(Interruptions)

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) 27 तारीख को दिल्ली मे लोगो पर लाठिया चलाई गई है आसू गैस छोडी गई है। इसके बारे मे ' (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैने किसी को काम रोको प्रस्ताव रखने की इजाजत नही दी है।

श्री भोगेन्द्र झा दिल्ली मे हुआ है, महिलाओ पर हुआ है, युवको पर हुआ है....

अध्यक्ष महोदय : मैने किसी को काम रोको प्रस्ताव रखने की इजाजत नही दी है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह सदन में आना चाहिए ....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: (ग्वालियर) काम रोको प्रस्ताव बिहार में हरिजन: महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, उसके

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बारे में है। आप अत्याचारों के विवरण को देखिए। उन के साथ बलात्कार किया गया है। उनको गर्म सलाखों — (व्यवधान) जब मामला पुलिस में गया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डाक्टरों ने भी ठीक रिपोर्ट नहीं दी। यह केन्द्र का विषय है —

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): डी एस० पी० ने जा कर खुद रेप करवाया। क्या कभी हरिजन लड़कियों की इज्जत की रक्षा होगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय आप संविधान की इस धारा को देखें :

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

यह मामला केवल राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे पहले भी बिहार में मुंघेर में पुलिस थाने में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। सारी दुनिया में यह भारत के लिए बड़े कलंक की बात है। आप चर्चा का मौका दें। .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने हरिजन महिलाओं के बारे में जिक्र किया है। एडजर्नमैंट मोशन से पहले आपके मेरे पास पांच सात नोटिस 377 के तहत आए थे। उसकी मैंने इजाजत दे दी थी। अब आपने जो कह दिया है उसको मिनिस्टर के पास भेजेंगे। जो जवाब आएगा वह आपके सामने रखेंगे। बहस करने की जरूरत होगी तो बहस करेंगे। पूरे हालात आ जाने दें, पूरे फैक्ट्स आ जाने दें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय): यह एडजर्नमेंट मोशन के लिए उपयुक्त विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देने को तैयार हूं। आप अपनी तारीख देख लीजिए।

श्री मधु लिमये (बांका): क्या बहस या काम रोको या कालिंग एटेंशन इन में से किसी की भी आप इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय : 377 में दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि फैक्ट्स आ जाएं। एडजर्नमेंट मोशन में आप मत पड़िये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार असेम्बली में फैक्ट्स आ गए हैं। स्पीकर ने माना है कि अत्याचार किए गए हैं और पुलिस देखती रही। सरकार की निन्दा करने का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : हरिजनों के बारे में रेफ़ेंस की इजाजत दे देता हूं। मिनिस्टर का जवाब जब आएगा आपके सामने रख दूंगा। अगर आप उस पर बहस करना चाहेंगे तो बहस की जा सकती है और अगर कालिंग एटेंशन चाहेंगे तो उसकी इजाजत दे दूंगा।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The observation of the Speaker of Bihar Assembly should be an eye-opener, rebuking the Government.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : This means that the Assembly is already seized of it.

बुरी बात नहीं है कि बिहार असेम्बली में आए। दे आर सीज्ड आफ इट।

कार्लिंग एटैंशन चाहेंगे तो उसकी इजाजत दे सकूगा । कैसा, तो आने दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कमिश्नर फार शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट भी आप मगाए । मधुबनी मे जाए और वह देखे कि क्या हुआ है और सदन को रिपोर्ट दे । वह पार्लियामैंट के प्रति जिम्मेदार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट मगवा लगा ।

13.18 hrs.

RE USE OF TEAR GAS ON DEMONSTRATORS IN DELHI

अध्यक्ष महोदय : अब दिल्ली मे जो डैमस्ट्रेशन हुआ और आसू गैस छाडी गई है वह कैसे पार्लियामेट मे आ जाए

श्री भोगेन्द्र झा राजधानी (जयनगर) दिल्ली मे जलूस निकलेगा शान्तिपूर्ण और उस पर आसू गैस छोडी जाएगी और लाठिया चलाई जाएगी और यह यहा एलाउ नही होगा तो कहा होगा ?

श्री ज्योति मय बसु डायमड हार्बर जंगल राज है ।

श्री भोगेन्द्र झा शान्तिपूर्ण प्रदर्शना पर ऐसा होगा तो शान्ति नही रहेगी । कृपा करके आप मौका दे और इसको एलाउ करे । लोग चुप नही रहेगे । जो दिल्ली मे हुआ है वह सारे देश मे होगा । लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करेगे और उन पर आप आसू गैस चलाएंगे, लाठिया चलाएंगे तो यह नहीं चलेगा । आप कालिंग एटैंशन इसको एलाउ करे और सदन मे आने दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) दिल्ली मे असैम्बली नही है । कानून और व्यवस्था के लिए पार्लियामेट जिम्मेदार है, केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है ।

अध्यक्ष महोदय डे टुडे एडमिनिस्ट्रेशन और मेटेंस आफ आर्डर यह यहा कैसे आएगा ।

All I can do is to send your protest to the Home Minister and ask him to make a statement

SHRI PILOO MODY (Godhra) If the procedure is that the Minister should make a statement, then he should have *suo motu* come to make that statement and not after we have brought the matter to the notice of the House, after we have agitated so much on it

MR SPEAKER I suggest a *via media* What they say, I will send it to him I shall allow two or three members

SHRI PILOO MODY The Minister should have come out with a statement on his own and not after my friends have raised it After they have demanded every type of motion in existence, you say, 'I will ask the Minister to make a statement' It does not make any sense We must have a discussion first before the Minister can reply

MR SPEAKER I will allow two or three members

SHRI JYOTIRMOY BOSU I want to bring to the notice of the House the atrocities that are committed on Harijans particularly on women, almost every day It happened in Banda district, then in Monghyr district.

MR SPEAKER You had already made your point earlier.